पूर्ण पीठ

श्री एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश, श्री पी. सी. जैन और श्री एस. सी. मित्तल, न्यायाधीश।

आई. एस. गोयल और अन्य,—याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,—प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 2018 का 1981,

3 मार्च, 1983

पंजाब सेवा इंजीनियर, वर्ग-1, पी.डब्लू.डी. (बी एंड आर शाखा) नियम, 1960—नियम 6(ए), 9 और 22—वर्ग-1 सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति–विश्वविद्यालय की डिग्री न होने वाले वर्ग-2 सेवा के सदस्यों को वरिष्ठता के आधार पर वर्ग-1 में पदोन्नत किया गया–डिग्री रखने की आवश्यकता उनके मामले में सामान्य रूप से माफ की गई–ऐसी माफी–नियम 6(ए) के प्रावधान के तहत क्या अनुमति योग्य है–नियम 6(ए)—क्षेत्राधिकार का–माफी का मामला–क्या प्रत्येक अधिकारी के मामले में विशेष रूप से विचार किया जाना आवश्यक है–नियम 22—क्या लागू होता है।

यह माना गया है कि पंजाब सेवा इंजीनियरों कक्षा-I, P.W.D. (B & R शाखा) नियम, 1960 के नियम 6(अ) का समग्र दृष्टिकोण यह बड़ा इरादा प्रकट करता है कि सामान्य नियम के रूप में, कक्षा-I सेवा में नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय की डिग्री धारकों को होनी चाहिए जिसका एक अपवाद संकीर्ण और विशिष्ट शर्तों में प्रदान किया गया है। यह निर्विवाद है कि कक्षा-I सेवा, जो इंजीनियरिंग सेवाओं के शिखर पर है, दोनों कुशल और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसलिए, अकादमिक योग्यताओं के संबंध में एक विश्वविद्यालय की डिग्री का निर्धारण और कक्षा-II से पदोन्नति के मामले में, वहां पूर्ण आठ वर्षों की सेवा का अनुभव और नियम 15 के अंतर्गत प्रदान की गई प्रावधिक परीक्षा का उत्तीर्ण करना, अनिवार्य किया गया है। प्रतीत होता है कि नियमों के निर्माताओं का इरादा नहीं था कि जिन व्यक्तियों के पास एक विश्वविद्यालय डिग्री की बुनियादी अकादमिक योग्यता नहीं है, उन्हें कक्षा-I सेवा में नियुक्त किया जाए। वे नहीं चाहते थे कि गैर-स्नातक इंजीनियर बाद में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या मुख्य इंजीनियर बनें। यह बात नियम 9 के संदर्भ से समर्थित है जो सेवा के भीतर पदोन्नति की बात करता है। नियम 9 के प्रावधान के अनुसार, यहां तक कि

जिन व्यक्तियों के मामले में नियम 6(ए) में उल्लिखित योग्यताओं को माफ किया गया है, वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या उससे ऊपर के पदों के लिए पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे आवश्यक योग्यताएं प्राप्त नहीं कर लेते। इंजीनियरिंग सेवा के उच्चतम स्तर के पदों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता, इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होती है। यह उल्लेखनीय है कि जनहित न तो नियम 6(ए) की आवश्यकता है और न ही उसका प्रावधान है, और ये शब्द वहां पाए नहीं जाते। सटीक रूप से कहें, तो यह किसी विशेष अधिकारी का मामला ही है जो सरकारी योग्यता माफी की शक्ति को आकर्षित करता है, और कुछ नहीं। यह केवल तभी है जब इस मूलभूत पूर्व-आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है कि वर्ग-२ सेवा के एक विशेष अधिकारी के मामले पर विचार करते हुए माफी का प्रयोग किया जाता है, न कि सामान्य आदेश में व्यक्तियों की सामूहिक या संगठनात्मक हित में। इसलिए, अपने आप में, सेवा की आवश्यकताएं या अधिक इंजीनियरों की प्रशासनिक मांग स्वयं में एक प्रासंगिक विचार नहीं होगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 6(ए) के पैरामीटर के भीतर बने रहने के लिए, विश्वविद्यालय की डिग्री की निर्धारित योग्यताओं की माफी को केवल विशेष अधिकारी के व्यक्तिगत विचार पर आधारित किया जा सकता है। वास्तव में यह केवल एक विशिष्ट अधिकारी की विशेष और विशिष्ट सेवाएं ही हैं जो सरकारी योग्यता माफी की शक्ति के आह्वान के लिए पुकारती हैं।

(पैराग्राफ 6 और 8)

यह निर्णय दिया गया है कि नियमों के नियम 22 में सरकार की नियमों में ढील देने की सामान्य शक्ति निहित है। ढील देने के लिए यह एक सामान्य नियम है जो नियम 6(ए) के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान की गई निर्धारित योग्यताओं की छूट के विशिष्ट मामले में लागू या आकर्षित नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि विशिष्ट नियम सामान्य नियमों को बाहर करते हैं। निर्धारित योग्यताओं की छूट के उद्देश्य के लिए, नियम 6(ए) के प्रावधान में विशिष्ट और विशेष प्रावधान है जो नियमों के नियम 22 के तहत सामान्य ढील देने की शक्ति के संचालन को बाहर करता है।

(पैराग्राफ 7)

एकल न्यायाधीश द्वारा इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपा गया था, जिसमें माननीय श्री जस्टिस एम. एम. पंच्छी ने 31 मई, 1982 को इस मामले में शामिल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का फैसला करने के लिए बड़ी पीठ को संदर्भित किया था। बड़ी पीठ जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस. एस. संधावालिया, माननीय श्री जस्टिस पी. सी. जैन और माननीय श्री जस्टिस एस. सी. मित्तल शामिल थे, ने अंततः इस मामले का निर्णय 3 मार्च, 1983 को किया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में प्रार्थना की गई थी कि सर्टियोररी, मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए: —

(i) मामले के पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए;

(ii) अनुलग्नक पी-1 पर आदेश को निरस्त किया जाए;

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित किया जाए कि वे अधिकारियों को वर्ग 1 के पद पर पदोन्नत करें उनके नामों को हरियाणा लोक सेवा आयोग से स्वीकृत कराने के बाद;

(iv) यह माननीय न्यायालय वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि के स्वरूप में सभी परिणामी राहत भी प्रदान करे;

(v) आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के निपटान के अधीन अनुलग्नक पी-1 पर आदेश का संचालन रोका जाए;

(vi) प्रतिवादी संख्या 1 को डिप्लोमा धारकों को वर्ग 1 के पद पर पदोन्नत करने से रोका जाए क्योंकि वे कार्यकारी इंजीनियरों के पदों पर आधारभूत डिग्री योग्यता के अभाव में अयोग्य हैं जो राज्य सरकार की विकास गतिविधियों के कारण बहुत जल्दी बनने वाले हैं;

(vii) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को प्रदान की जाए।

(viii) प्रतिवादियों को मोशन का नोटिस सेवा करने से छूट दी जाए क्योंकि मामला तत्काल प्रकृति का है और रोक के लिए प्रार्थना की गई है।

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित एस. सी. सिब्बल और ईश्वरी प्रसाद मरकन, अधिवक्ता।

कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित सी. एम. चोपड़ा और एस. एस. निज्जर निजी प्रतिवादियों की ओर से।

बी. एल. बिश्नोई, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा, राज्य की ओर से।

निर्णय

एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश

1. सरकारी शक्ति के वास्तविक आयाम और परिधि, जो वर्ग 1 सेवा की नियुक्ति के लिए अनिवार्य निर्धारित योग्यताओं की छूट देने के लिए है, जो पंजाब सेवा इंजीनियरों, वर्ग 1, पी.डब्लू.डी. (बी एंड आर शाखा) नियम, 1960 के नियम 6(ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त है– यह एक महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न है जिसने इस सेट के तीन सिविल रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ के समक्ष संदर्भित करने की आवश्यकता को जन्म दिया है।
2. चूंकि हम अपने आप को मुख्यतः उपरोक्त प्रश्न तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं, इसलिए केवल उन्हीं तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है जो इससे सीधे संबंधित हैं। ये तथ्य सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2018 का 1981 (आई. एस. गोयल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) से लिए जा सकते हैं। वहां के रिट याचिकाकर्ता इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्हें 1970-71 के वर्ष में हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क शाखा) की वर्ग II इंजीनियरिंग सेवा में विभिन्न तिथियों पर नियुक्त किया गया था। उनका मूल दावा यह है कि, डिग्रीधारक होने के नाते वे ही मुख्यतः पंजाब सेवा इंजीनियर, वर्ग 1, पी.डब्लू.डी. (भवन और सड़क शाखा) नियम, 1960 के नियम 6 के तहत इंजीनियरों की वर्ग 1 सेवा में पदोन्नति के लिए प्राथमिक रूप से पात्र हैं। उनकी ओर से प्रस्तुत मुख्य शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 10, जो बी.एससी. इंजीनियरिंग डिग्री या उसके समकक्ष नहीं रखते हैं, फिर भी उन्हें वर्ग 1 सेवा में पदोन्नत किया गया है, जैसा कि अनुलग्नक पी/1 में दिखाया गया है, निर्धारित योग्यताओं में सामान्य ढील देकर। यह बताया गया है कि ये प्रतिवादी केवल डिप्लोमा धारक हैं जिन्हें मूल रूप से सेक्शनल अधिकारियों/ड्राफ्ट्समैन के रूप में भर्ती किया गया था और बाद में 1969-70 में सब-डिवीजनल इंजीनियरों के रूप में कार्यरत किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से नियम 6 के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है, हालांकि नियम 8 के उल्लंघन का भी समान रूप से दावा किया गया है। हालांकि, चूंकि हम नियम 8 की प्रासंगिकता या उल्लंघन पर ध्यान देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इसलिए उसके संबंध में आवरणों का उल्लेख करना अनावश्यक है। फिर यह दावा किया गया है कि वर्ग 1 के 15 रिक्त पदों में से 8 व्यक्तियों, जो डिप्लोमा धारक हैं, को उनकी योग्यताओं में सामान्य और रूटीन ढंग से छूट देकर वर्ग 1 में पदोन्नत किया गया है, जो कि नियमों के नियम 6(ए) के प्रावधान के पत्र और भावना दोनों का उल्लंघन करता है।
3. उत्तरदाताओं की आपत्तिजनक कार्रवाई के पृष्ठभूमि के रूप में, पैराग्राफ 11 में यह बताया गया है कि 1975 से हरियाणा सरकार ने वर्ग 1 सेवा के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को छूट देने की

इस शक्ति का सामान्य और रूटीन ढंग से उपयोग किया है। यह आरोप लगाया गया है कि इंजीनियरिंग डिग्री न रखने वाले व्यक्ति और इस प्रकार वर्ग 1 सेवा के लिए अयोग्य होने के बावजूद, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर उन लोगों के समान मानकर पदोन्नत किया जा रहा है जो डिग्री योग्यता रखते हैं। नियम 6 के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व, अनुलग्नक पी/2 का उल्लेख किया गया है, और इसके अलावा पूर्व के कई मामलों में किए गए टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया गया है, जहां नियम 6 के वास्तविक आयाम और सरकारी छूट देने की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है।

4. उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में, तथ्यात्मक स्थिति को व्यापक रूप से विवादित नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10 केवल डिप्लोमा धारक हैं, लेकिन इस बात से इंकार किया गया है कि उन्हें B.Sc. इंजीनियरिंग डिग्री के अभाव में कक्षा। सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाए। सरकार की योग्यताओं के शिथिलीकरण की शक्ति पर जोर दिया गया है जिसके लिए उत्तरदाताओं के अनुसार आगे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। वापसी के पैरा 5, 8, 9, 11, 14 और 15 (i) में, जो बात उजागर की गई है वह यह है कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10, याचिकाकर्ताओं के सीनियर होने के नाते, उनके पहले विचार किए जाने चाहिए और उन्हें याचिकाकर्ताओं से पहले पदोन्नति का अधिकार है, यदि वे अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं। उत्तरदाता-राज्य द्वारा यह कहा गया है कि अनुलग्नक P/2 को अस्वीकार कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं का मामला केवल तब विचार किया जाएगा जब उनकी कक्षा। सेवा में पदोन्नति के लिए बारी आती है, उनके सभी वरिष्ठ सहकर्मियों की सूची को समाप्त करने के बाद, स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बावजूद कि क्या उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या नहीं। तब यह कहा गया है कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10 का मामला वरिष्ठता के क्रम में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले अन्य लोगों के साथ विचार किया गया था और चूंकि उनके मामले में एकमात्र समस्या डिग्री योग्यता की थी, इसलिए उसे नियम 6 (ए) के तहत माफ कर दिया गया था।वापसी के पैरा 14 में, यह स्वीकार किया गया है कि कक्षा II सेवा में आवश्यक अनुभव रखने वाले, डिग्री योग्यता वाले 60 अधिकारी उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें उनके बारी के अनुसार तब पदोन्नत किया जाएगा जब उनके वरिष्ठ सहकर्मियों की सूची समाप्त हो जाती है। अंत में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता, उत्तरदाता संख्या 3 से 10 के जूनियर होने के नाते, केवल तब विचार किए जाएंगे जब उनकी बारी आती है, उनके वरिष्ठों की पदोन्नति के बाद।

5. 5. इस मामले में विवाद अनिवार्य रूप से नियम 6 की विशेष भाषा पर केंद्रित होता है और चूंकि नियम 22 के तहत सामान्य शिथिलीकरण शक्ति का भी कुछ संदर्भ दिया गया था, इसलिए शुरू

में दोनों प्रावधानों के संबंधित भागों को उद्धृत करना उचित प्रतीत होता है ताकि संदर्भ की सुविधा हो:

"6. योग्यताएँ।–कोई भी व्यक्ति तब तक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह–(ए) नियमों की परिशिष्ट B में निर्धारित एक विश्वविद्यालय डिग्री या अन्य योग्यताएँ न रखता हो, बशर्ते कि सरकार किसी विशेष अधिकारी के मामले में जो कक्षा II सेवा से संबंधित हो, इस योग्यता को माफ कर सकती है।

(b) ' * * *"

"22. शिथिलीकरण की शक्ति।–(1) जहां सरकार यह संतुष्ट होती है कि इन नियमों में से किसी एक का संचालन किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई पैदा करता है, वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन छोड़ सकती है या शिथिल कर सकती है, जैसा कि वह उस मामले को न्यायपूर्ण और समान तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे।"

नियम 6(ए) का स्पष्ट विश्लेषण यह संकेत करता है कि इसके निर्माताओं ने स्पष्ट शब्दों में यह आवश्यकता निर्धारित की है कि कक्षा। सेवा में नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय डिग्री या नियमों की परिशिष्ट B में निर्धारित अन्य योग्यताएं पूर्वापेक्षाएं होंगी। जिस भाषा में नियम को जानबूझकर रखा गया है, वह मुझे न्यूनतम योग्यताओं के एक मात्र प्रावधान से कुछ ज्यादा लगती है। 'जब तक' शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है। यह केवल एक आवश्यकता का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि विश्वविद्यालय डिग्री न रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के खिलाफ एक बाधा भी तय करता है। इसलिए, नियम का इरादा और सामान्यता स्पष्ट रूप से यह है कि कक्षा । सेवा में पदों को इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय डिग्री रखने वाले व्यक्तियों द्वारा संभाला जाना है। हालांकि, मूल नियम के लिए विशिष्ट शर्तों में एक अपवाद प्रदान किया गया है, जो स्वयं प्रावधान में है। इस अपवाद का सहारा लेने की सीमा, या दूसरे शब्दों में, प्रावधानित योग्यताओं की छूट, खुद को एक प्रावधान के रूप में नियम में शामिल किया गया है। यह शब्दों में यह कहता है कि योग्यताओं को कक्षा II सेवा के किसी विशेष अधिकारी के मामले में माफ किया जाना है। अनिवार्य रूप से छूट को एक विशेष प्रत्याशी की विशेषताओं से संबंधित किया जाना है।

6. नियम 6(ए) के नियमों की समग्र दृष्टि से एक बड़ा इरादा प्रकट होता है कि एक सामान्य नियम के रूप में, कक्षा । सेवा में नियुक्ति पाने वाले विश्वविद्यालय डिग्री धारक होने चाहिए, जिसमें संकीर्ण और विशिष्ट शर्तों में एक अपवाद प्रदान किया गया है। यह हमारे सामने विवादित नहीं हो सकता था कि कक्षा। सेवा, इंजीनियरिंग सेवाओं के शीर्ष पर होने के नाते, दोनों कुशल और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए, अकादमिक योग्यताओं के संबंध में एक विश्वविद्यालय डिग्री का प्रावधान और कक्षा ॥ से पदोन्नति के मामले में, वहां में पूर्ण आठ वर्ष की सेवा का अनुभव और नियम 15 के अनुसार प्रावधानीय परीक्षा का उत्तीर्ण करना, आवश्यक बनाया गया है। स्पष्ट रूप से, नियमों के निर्माताओं का इरादा नहीं था कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय डिग्री की मूल अकादमिक योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें कक्षा । सेवा में नियुक्त किया जाए। वे नहीं चाहते थे कि गैर-स्नातक इंजीनियर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या चीफ इंजीनियर बनें। इसकी पुष्टि नियम 9 के नियमों के संदर्भ से होती है जो सेवा के भीतर पदोन्नति की बात करता है। नियम 9 के नियमों के प्रावधान में, शब्दों में यह निर्धारित किया गया है कि जिन व्यक्तियों के मामले में नियम 6(ए) में उल्लिखित योग्यताओं को माफ किया गया था, वे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या उससे ऊपर के पदों के लिए पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक वे आवश्यक योग्यताएं नहीं प्राप्त कर लेते। इस प्रकार, इंजीनियरिंग सेवा के उच्चतम स्तरों में पदों के लिए विश्वविद्यालय डिग्री की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होती है।
7. इससे आगे बढ़ने से पहले नियमों के नियम 22 की प्रासंगिकता या अन्यथा को स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। जैसा कि स्पष्ट है, यह सरकार में नियमों की सामान्य शिथिलीकरण शक्ति का प्रतीक है। मैं दृढ़ता से इस विचार को लेने की ओर झुका हुआ हूँ कि यह नियम जो शिथिलीकरण के लिए एक सामान्य है, नियम 6(ए) के तहत निर्धारित योग्यताओं की छूट के विशिष्ट मामले में लागू या आकर्षित नहीं होता है। यह स्वाभाविक है कि विशेष सामान्य को बाहर करता है। प्रावधानित योग्यताओं की छूट के उद्देश्य के लिए, नियम 6(ए) का प्रावधान विशेष और निर्दिष्ट प्रावधान है जो नियम 22 के तहत सामान्य शिथिलीकरण शक्ति के संचालन को बाहर करता है। परिणामस्वरूप, न्यायपूर्ण और समान तरीके से मामले के साथ व्यवहार करने की व्यापक विचारनाएँ और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए एक नियम के साथ छोड़ने की शर्तें जो नियम 22 में वर्णित हैं, वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होती हैं। नियम 6 (ए) के प्रावधान के विशेष प्रावधानों को देखते हुए, हमें नियमों के सामान्य नियम 22 का आगे आह्वान करने या इसका सहारा लेने के लिए कोई कारण या विवशता नहीं दिखाई देती है, जब नियम 6(ए) के तहत छूट के लिए एक विशिष्ट प्रावधान मौजूद है।

8. प्रतीत होता है कि उत्तरदाता-राज्य नियम 6(ए) के नियमों के सही अर्थ के बारे में कुछ गलतफहमी में है। आपत्तिजनक आदेश, अनुलग्नक P/1 के पैरा 3 से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10 के मामले में डिग्री योग्यताओं की शर्तों को जनहित में शिथिल किया गया है। यह उजागर करने योग्य है कि जनहित नियम 6(ए) की आवश्यकता या प्रावधान नहीं है और इसके शब्द वहां कहीं नहीं पाए जाते हैं। संकेत करने के लिए, यह केवल एक विशेष अधिकारी का मामला है जो सरकारी छूट की शक्ति को आकर्षित करता है और कुछ और नहीं। केवल तब जब यह मूल पूर्व-शर्त पूरी होती है, तब छूट का उपयोग कक्षा II सेवा के एक विशेष अधिकारी के मामले पर विचार करने पर किया जाना चाहिए और व्यक्तियों के सामूहिक या संगठन में जनहित में एक सामान्य आदेश में नहीं। इसलिए, स्वयं में, सेवा की आवश्यकता या अधिक इंजीनियरों की प्रशासनिक मांग अपने आप में एक प्रासंगिक विचार नहीं होगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 6(ए) के नियमों के पैरामीटर के भीतर रहने के लिए, विश्वविद्यालय डिग्री की प्रावधानित योग्यताओं की छूट केवल एक विशेष अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से विचार करने की आधारभूत नींव पर ही आधारित की जा सकती है। वास्तव में, यह केवल एक विशिष्ट अधिकारी की विशेष और विशिष्ट सेवाएं हैं जो सरकारी छूट की शक्ति के आह्वान के लिए कहती हैं। आपत्तिजनक आदेश, अनुलग्नक P/1, जो 8 अधिकारियों के साथ एक समूह में संबंधित है और अपने आप को जनहित पर आधारित दिखाते हुए, इस प्रकार नियम 6(ए) के नियमों के इरादे से परे है और इस स्कोर पर एक गंभीर कानूनी खामी से ग्रस्त है।

9. उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों के पक्ष में यह जाता है कि उन्होंने स्वयं यह रुख अपनाया कि नियम 6(ए) के नियम सचमुच व्यक्तिगत मामले की विशिष्टता की कल्पना करते हैं और जनहित में कई पदों या व्यक्तियों के समूह के लिए शैक्षिक योग्यताओं की कोई सामान्य छूट नहीं। इसलिए, छूट को नियम 6(ए) के नियमों के संकीर्ण दायरे के भीतर विशिष्ट विचारों पर आधारित किया जाना चाहिए। मामला इस प्रकार से संकुचित हो गया था कि उत्तरदाता-राज्य की ओर से लिए गए रुख की और रिकॉर्ड की जांच की जाए, जो हमारे परीक्षण के लिए सहज उपलब्ध कराया गया था। इससे यह पता चलता है कि कक्षा II सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए नियम 8 के नियमों के तहत गठित एक स्क्रीनिंग समिति ने उनके मामलों को वरिष्ठता के क्रम में नियमित रूप से विचार किया, चाहे विश्वविद्यालय डिग्री रखने की योग्यता नियम की पात्रता हो या नहीं। इसके बाद, इसने पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त पाए गए सभी अधिकारियों के मामलों में योग्यताओं की छूट की सिफारिश की। यह तथ्य से स्पष्ट है कि कक्षा। के 15 रिक्तियों में से, जितने

8 डिप्लोमा धारक, जिनके पास विश्वविद्यालय डिग्री नहीं थी, उन्हें प्रावधानित योग्यताओं की छूट की सिफारिश की गई और अनुमति दी गई थी।

10. 10. अब, राज्य की वापसी के पैरा 5, 8, 9, 11, 14 और 15 (i) में दिए गए स्पष्ट दावों और उपर्युक्त रिकॉर्ड की परीक्षा से यह संदेह की कोई भी बात नहीं रह जाती है कि कक्षा ॥ सेवा के मौजूदा सदस्यों को वरिष्ठता के सामान्य क्रम में विचार किया गया था, चाहे वे इंजीनियरिंग की विश्वविद्यालय डिग्री रखने वाले हों या न हों। मूलतः, इसलिए, विश्वविद्यालय डिग्री रखने वाले अधिकारी और जो नहीं रखते थे, उन्हें पूरी तरह से समान और वस्तुतः एक-दूसरे के गणितीय समतुल्य माना गया था। उन सभी मामलों में जहां अधिकारियों का रिकॉर्ड उनकी पदोन्नति को सही ठहराता था, समिति ने उनकी कक्षा। सेवा में नियुक्ति की सिफारिश की, चाहे वह सरल रूप से हो या डिग्री की योग्यता को छोड़कर। संक्षेप में, कक्षा ॥ सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए समान विचार प्रबल था, चाहे वे डिग्री-धारक हों या गैर-डिग्री-धारक।

11. उत्तरदाता-राज्य द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई को याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर जोरदार तरीके से आक्षेपित किया गया है (मेरे विचार में, सही तरीके से) क्योंकि यह नियम 6(ए) के नियमों के अक्षर और भावना दोनों का पूर्ण नकार है। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस नियम की भाषा के मद्देनजर, कक्षा। सेवा में नियुक्ति के लिए पात्रता इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय डिग्री के धारण करने द्वारा निर्धारित होती है। यदि कक्षा ॥ सेवा में किसी पद का धारक अनुभव की अन्य शर्तों और विभागीय परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने को पूरा करता है और वह विश्वविद्यालय डिग्री धारक है, तो वह कक्षा। में पदोन्नति के लिए पात्र है। इसके विपरीत, यदि वह ऐसी डिग्री नहीं रखता है, तो वह सामान्य रूप से इसके लिए पात्र नहीं है और इसलिए, उच्चतर सेवा में पदोन्नति के लिए विचार के लिए भी अनिवार्य रूप से हकदार नहीं है। इस प्रकार, इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय डिग्री धारक और जो ऐसी डिग्री नहीं रखते हैं, उन्हें नियम 6(ए) के नियमों द्वारा कक्षा। में नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए अलग-अलग वर्गों में रखा गया है। वे समान रूप से असमान पैर पर रखे गए हैं। इन असमानों को गणितीय रूप से समान मानने के लिए और उन्हें एक-दूसरे के साथ समतुल्य मानकर और केवल वरिष्ठता के आधार पर उन्हें कक्षा। सेवा में नियुक्त करना, इसलिए, नियमों के बहुत ही इरादे के विरुद्ध और उल्लंघन है।

12. फिर से, इसे दोहराना आवश्यक है कि नियम 6(ए) के मुख्य प्रावधान में स्पष्ट शब्दों में यह सामान्य निर्देश दिया गया है कि कक्षा। सेवा के नियुक्तियों में इंजीनियरिंग की डिग्री रखना अनिवार्य है। केवल एक विशिष्ट अपवाद के रूप में संकीर्ण सीमाओं के भीतर इस आवश्यकता की छूट को विशेष और व्यक्तिगत अधिकारी के मामले में अनुमति दी जानी है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है

कि सिद्धांत की सामान्यता इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय डिग्री का धारण होना है और इसके अपवाद के रूप में इसकी अनुपस्थिति है। इसलिए, डिग्री रखने वाले व्यक्तियों और जो नहीं रखते हैं, उन्हें केवल वरिष्ठता के आधार पर समान और समतुल्य मानने में, नियम के मूल सिद्धांत को न केवल नजरअंदाज किया गया है, बल्कि यदि कहा जाए तो, वास्तव में इसे उलट दिया गया है। रिकॉर्ड और उत्तरदाताओं के दावों के अनुसार, ऐसा लगता है कि गैर-डिग्री-धारकों के मामले में योग्यताओं की छूट को सामान्य नियम बना दिया गया है और ऐसी छूट का इनकार केवल एक मामूली अपवाद के रूप में किया गया है। उत्तरदाता-राज्य का रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कक्षा II सेवा के उन अधिकारियों, जिनके पास विश्वविद्यालय डिग्री नहीं है लेकिन औसत रिकॉर्ड जो उनकी पदोन्नति को बाधित नहीं करता, उन्हें नियमित रूप से योग्यताओं की छूट दी गई है। संक्षेप में, विशेष वैधानिक अपवाद की छूट जो एक विशेष अधिकारी के संबंध में होती है, उसे सामान्य उपयोग का बना दिया गया है और सामान्य नियम कि कक्षा I के अधिकारी इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय डिग्री धारक होने चाहिए, वास्तव में भ्रामक और किसी प्रकार से अपवादी बना दिया गया है। यह एक दृष्टिकोण है जो स्पष्ट रूप से नियम 6 (ए) के नियमों के स्पष्ट प्रावधान के लिए विदेशी और अन्यथा है।

13. उत्तरदाता-राज्य के रुख से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उन्होंने मुख्य रूप से कक्षा II सेवा के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता के आधार पर खुद को टिकाया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10 याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हैं और बाद वालों को केवल तब विचार किया जाएगा जब उनके वरिष्ठ लोगों को पूरी तरह से विचार किया जा चुका होगा, चाहे उनके पास विश्वविद्यालय डिग्री हो या न हो। मैं इस संदर्भ में यह विचार रखने की ओर झुका हुआ हूँ कि दो विभिन्न वर्गों, विश्वविद्यालय डिग्री धारकों और गैर-डिग्री धारकों के बीच केवल वरिष्ठता का विचार करना, नियम 6 (ए) के नियमों के लिए पूरी तरह से विदेशी प्रतीत होता है। नियम 6 (ए) का आधार यह प्रतीत होता है कि केवल विश्वविद्यालय डिग्री धारक व्यक्ति मुख्य रूप से पात्र हैं और ऐसी डिग्री न रखने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता कम या शायद बिलकुल भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, मैं याचिकाकर्ताओं के रुख को सही मानते हुए यह विचार करता हूँ कि डिग्री-धारकों और गैर-डिग्री धारकों के अलग-अलग वर्गों के बीच केवल वरिष्ठता पर विचार करना नियम 6(ए) के लिए अन्यथा था और उत्तरदाता-राज्य द्वारा केवल वरिष्ठता पर आधारित निर्णय वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध था।

14. फिर, यह उजागर करना आवश्यक है कि जैसा कि नियम 6 (ए) में वर्तमान में है, कक्षा II सेवा के किसी अधिकारी की विशेष व्यक्तिगतता ही छूट की शक्ति को आह्वान करने का सच्चा आधार है।

केवल तब जब विशेष अधिकारी इतने असाधारण योग्यता का होता है कि वह आवश्यक अकादमिक योग्यता की अनुपस्थिति के बावजूद पहचान के लिए चिल्लाता है, तब सरकार डिग्री योग्यता के सिद्धांत की सामान्यता को छोड़ने का सहारा लेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया एक कुछ हद तक संभावित उदाहरण भाखड़ा बांध के आर्किटेक्ट श्री स्लोकम का था, जो कि विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर थे, फिर भी उनके पास विश्वविद्यालय डिग्री के रूप में कोई औपचारिक इंजीनियरिंग शिक्षा नहीं थी। यह बताया गया कि यह ऐसे ही प्रकृति के मामले होंगे, हालांकि स्पष्ट रूप से बहुत कम स्थान पर, जहां एक व्यक्तिगत अधिकारी के मामले की विशेषताएं पहचान और छूट नियम का सहारा लेकर उच्च रैंक में पदोन्नति के लिए खड़ी होती हैं। इसलिए, नियम 6 (ए) का प्रावधान केवल कक्षा ॥ सेवा के असाधारण उत्कृष्ट योग्यता वाले एक व्यक्तिगत अधिकारी के मामले में आकर्षित होता है।

15. अंत में, निर्माण के एक ठोस कैनन से भी सहायता मांगी जा सकती है। नियम 6 (ए) को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि योग्यताओं का प्रावधान सामान्य प्रावधान है जबकि इसकी छूट उसी के प्रावधान के रूप में है। जैसा कि प्रसिद्ध है, एक प्रावधान केवल मुख्य खंड को स्पष्ट करता है या उसे योग्य बनाता है और वह उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। उत्तरदाता-राज्य स्पष्ट रूप से इस प्रावधान (जो छूट नियम को प्रावधानित करता है) की व्याख्या उस तरीके से करना चाहता है जो वस्तुतः मुख्य खंड के आदेश को निष्प्रभावी कर देता है कि कोई भी व्यक्ति कक्षा। सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास विश्वविद्यालय डिग्री या अन्य समकक्ष योग्यताएं न हों।
16. उपरोक्त विस्तृत कारणों के आधार पर, मेरा स्पष्ट विचार है कि CWP 2018/1981 (I. S. Goel इत्यादि बनाम राज्य हरियाणा और अन्य) में उत्तरदाता संख्या 3 से 10 के पक्ष में की गई सरकारी कार्रवाई अनुचित है और इसे यहाँ निरस्त किया जाता है। इसमें अनुलग्नक P/1 के संबंधित पैरा 3 को परिणामस्वरूप निरस्त किया जाता है और उत्तरदाता संख्या 3 से 10 की, कार्यकारी इंजीनियरों के रूप में, पदोन्नति को यहाँ निरस्त किया जाता है। इस प्रकार, यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार बिना किसी लागत के आदेश के साथ स्वीकार की जाती है।
17. यह सामान्य आधार है कि CWP संख्या 3307 का 1980 (राजिंदर परशाद इत्यादि बनाम राज्य हरियाणा और अन्य) और C.W.P. संख्या 2632 का 1980 (एस. सी. कौरा और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य) में अन्य मुद्दे उठ सकते हैं। अब ये मामले उपरोक्त के प्रकाश में योग्यता पर निर्णय के लिए सीखे हुए सिंगल जज के पास वापस जाएंगे।

18. इस निर्णय के साथ विदाई लेते हुए, यह उचित है कि यह पूर्ण पीठ के संदर्भ की आवश्यकता ओ. पी. भाटिया और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य और एस. एस. देसवाल और अन्य बनाम मुख्य सचिव सरकार, हरियाणा और अन्य में कुछ कथित न्यायिक राय में विवाद के कारण प्रतीत होता है। हालांकि, हमारे सामने पक्षों के वकीलों ने एकमत से बताया कि एक करीबी विश्लेषण पर कोई न्यायिक राय का संघर्ष प्रकट नहीं होता है जो समाधान के लिए बुलाता है। यह अन्यथा एस. एस. देसवाल के मामले (ऊपर) के संदर्भ में स्पष्ट है जिसे स्पष्ट रूप से इसके विशेष तथ्यों पर मोशन स्टेज में तय किया गया है।

प्रेम चंद जैन, जे. - मैं सहमत हूँ।

एस. सी. मितल, जे. - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा